

सेवा में,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 10 / दिसम्बर, 2008

विषय:- गैर राणा ग्लोबल लि० को जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम मंगनीली में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल 7.566 हे० भूमि कय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-691/भूमि व्यवस्था - भू० कय - 8 दिनांक 26-8-08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गैर राणा ग्लोबल लि० का औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम मंगनीली तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार में कुल 7.566 हे० भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुवृत्त एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं (प्रति सलग्न) के अनुसार कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- कंटा धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंटा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि कयक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंटा द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय बिलेज के मंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसी कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा उसी प्रयोजन (इटीपीएल स्केम/लेड स्कीम प्लान की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है।

यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कम किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिए विद्युत, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-187 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति / जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति / जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्ण सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अतिथार वाले भूमिधर न हों।

6- शारंग द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शारंगदेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के रोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल इटीयेंटल स्टेशनल स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु किया जायेगा।

9- कय की जाने वाली भूमि का भू उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जीएसआई0जी0सी0धारण 2005 में दिये गये नियमों / मानकों के अनुसार राक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्लान के अनुसार राइक का निर्माण किया जायेगा।

10- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्य का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

11- इस स्वीकृति की विद्युत संयोजन के लिए स्वीकृति नहीं माना जायेगा। प्रस्तावित इकाई नूँकि एक उच्च विद्युत खपत इकाई है, उक्त उच्च विद्युत अथवा उसके अधीन संबंधित संस्था की प्रक्रियानुसार विद्युत संयोजन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12- सम्बन्धित इकाई को भू-उपयोग करने से पूर्ण सक्षम ऐजेन्सी (विनियमित श्रेष्ठ प्राधिकरण / विशंग क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी, तभी इकाई द्वारा भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु किया जा सकेगा।

13- किसी दशा में प्रस्तावित केंद्रों को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सर्वाधिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय का तत्काल अद्वैत असाध्य सीमांकन कर दिया जाये।

14- भूमि का विक्रय अपारिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त अनुमति नहीं होगा एवं ऐसी प्रथा में विक्रय किया जाने हेतु सम्बन्धित शासन की अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिका व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0-4123 /संमदिनांकत/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त गिन्तुओं का विन्यासबद्ध सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल गण्डक, पीछी।
- 6- निदेशक, उद्योग, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पटलनगर देहरादून।
- 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीआ, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 8- श्री शाह भवाज राणा, निवासी न्यू हाउस मेरठ रोड मुजफ्फरनगर।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 10- प्रहारी गीडिया केंद्र, सचिवालय।
- 11- मार्ट फाईल।

आज्ञा से

(सन्ताप न-361)
अ-सचिव